Abm Knowledgeware e-governance solutions & services

helping the nation to be corruption-free

'e-Nagarpalika' in MP launched on 1st April 2017 made its first step against corruption in BHOPAL, dainik bhaskar, 15 June 2017

रिटायर्ड अफसर
कई सवाल छोड़
टना का सबक ये

है कि नौकर हो या ड्राइवर, उन्हें काम पर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन हर हाल में कराएं। इस दिशा में पुलिस को भी पहले से ज्यादा चौकस रहने की जरुरत है।

दैनिक भास्कर
भोपाल, गुरुवार, 15 जून, 2017

ऑडिट... ई-नगर पालिका सिस्टम

लागू हुए दो माह पूरे नकद भुगतान बंद

ई-गवर्नेंस ने लगाई करप्शन पर लगाम

- नगरीय निकायों की सभी सेवाएं ऑनलाइन होने से आसान हो गए नागरिकों के काम
- सिस्टम लागू होने के बाद पकड़ में आए फर्जी भुगतान के कई मामले

राजेश शर्मा | भोपाल

प्रदेश सरकार ने एक अप्रैल 2017 से ई-नगर पालिका सिस्टम लागू कर दिया है। अब नगरीय निकायों की सभी सेवा व सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं। जिससे नागरिकों के काम भी आसान हो गए हैं, लेकिन नकद भुगतान बंद होने की इस व्यवस्था से नगर पालिका व परिषद अध्यक्षों के कमीशन पूरी तरह बंद हो गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना हो या फिर मकान बनाने के लिए नक्शा स्वीकृत करना। ऐसे सभी काम अब ऑनलाइन हो रहे हैं। इस योजना को लागू हुए दो माह से ज्यादा का समय बीत चुका है। बावजूद इसके सिस्टम पूरी तरह पटरी पर नहीं आ पा रहा है। कारणों का पता लगाने के लिए दैनिक भास्कर ने जब पड़ताल की तो पाया कि कैशलेस व पेपरलेस इस सिस्टम का कुछ निकायों के सीएमओ और इंजीनियर भी अप्रत्यक्ष तौर पर विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सिस्टम लागू होने के बाद फर्जी भुगतान के कई मामले पकड़े गए हैं। कई निकायों में वर्क ऑर्डर के मुताबिक सामग्री सप्लाई नहीं होने के कारण भुगतान अटक गए हैं।

अब बंद हो गई पहले काम बाद में वर्क ऑर्डर की प्रथा

ज्यादातर निकायों में पहले काम बाद में वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रथा पर रोक लग गई है। पहले अध्यक्ष नियमों को दरकिनार कर पहले काम करा लेते थे और बाद में परिषद से स्वीकृति लेकर वर्क ऑर्डर जारी कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है।

कैशलेस व पेपरलेस सिस्टम का अप्रत्यक्ष विरोध

130 दिन रोकी पेमेंट प्रभारी सीएमओ पकड़ाए

रामशाहवाद में पेयजल योजना के 8 लाख रुपए के काम ठेकेदार से कराए, लेकिन प्रभारी सीएमओ राकेश मिश्रा ने 130 दिन पेमेंट अटका कर रखा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग में अफसरों ने इसे पकड़ लिया।

धार सीएमओ चेक से भुगतान करते पकड़ाए

धार नपा के सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित ठेकेदारों को चैक से पेमेंट करते पकड़े गए। निर्माण कार्यों का एस्टीमेट एप्रूवल से लेकर टेक्नीकल जानकारी ऑनलाइन दिखाई दे रही थी, लेकिन पेमेंट की कोई जानकारी फीड नहीं थी।

ढाई लाख की सामग्री का बिल छह लाख

शाजापुर की पोलायकलां परिषद ने 6 लाख का वर्क ऑर्डर जारी किया। सामग्री 2.5 लाख की हुई। ठेकेदार ने कि 6 लाख का लगाया। पता चला, परिषद अध्यक्ष ममता चौधरी ने पेमेंट के लिए सीएमओ पर दबाव बनाया था।

ऑनलाइन पेमेंट होने से चेक जेब में लेकर नहीं घूम पा रहे अध्यक्ष

कई निकायों में सीएमओ से हस्ताक्षर करा कर नपा व परिषदों के अध्यक्ष चैक अपने पास रख लेते थे और सुविधानुसार ठेकेदारों को देते थे, लेकिन ई नगर पालिका सिस्टम लागू होने के बाद अध्यक्ष व सीएमओ के डिजिटल सिग्नेचर से ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है।

बजट जितना स्वीकृत हुआ, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं

नगरीय निकायों में जिस विभाग को जितना बजट स्वीकृत किया गया है, वे उसका किसी अन्य काम में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी सड़कों के लिए स्वीकृत बजट को पानी की पाइप लाइन बदलने में खर्च नहीं कर पा रहे हैं।

जल्दी पटरी पर आ जाएगा पूरा सिस्टम

- सीएम ने प्रदेश के नागरिकों के लिए ई-गवर्नेंस को सर्वव्यापी माध्यम बनाने का संकल्प लिया है। हालांकि सिस्टम में कुछ कमियां रह गई हैं। जिसे पूरा कर सिस्टम पटरी पर लाया जा रहा है। सिस्टम लागू होने के दो माह पूरे होने पर राज्य स्तर पर आंकलन किया गया है। नागरिकों की समस्याओं का निराकरण समय सीमा में हो रहा है, लेकिन निकायों के अंदरुनी सिस्टम में सुधार की जरुरत है। - विवेक अग्रवाल, कमिश्नर नगरीय प्रशासन